प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सहायता की राशि को खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वित्त मंत्रालय पहले ही राज्य सरकारों को तीन बराबर किस्तों में 75% निधियां जारी कर चुका है। राज्यों को 25% अंतिम किस्त खर्च की प्रगति और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन को ध्यान में रखकर जारी की जाएगी।

मध्य प्रदेश में किसानों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजनाएं

1451. **श्री अजीत जोगी:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई तथा उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों को पर्याप्त विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में कोई योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Assistance to Andhra Pradesh for Resurvey of Land

1452. DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
DR. D. VENKATESHWAR RAO:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the outcome of the meeting of State Revenue Ministers held in New Delhi on January 28, 1997;

(b) the action taken to publish village-wise land records with survey numbers and the names of occupants in all the states;

(c) whether the Andhra Pradesh Government has sought an assistance of Rs. 120 crores to take up resurvey of land; and

(d) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) The meeting of the State Revenue Minister's held in New Delhi on January 28, 1997 adopted 33 valuable recommendations which include time bound distribution ceiling surplus land, Bhoodan land and Government Wastelands, involvement of Panchayati Raj Institutions in land reforms and land revenue administration, restoration of alienated tribal land, updation of land records including taking up cadastral survey & settlement operations in States where the same is overdue and implementation of various other land reforms measures.

(b) Publication of village-wise land records with survey numbers and the names of occupants is done during the revisional survey settlement operation, whenever the same is taken up by any State. The State laws prescribe different periodicity for different States to take up such revisional survey settlement operations, and hence, it cannot be taken up in all the States in a particular year or even in a particular Five Year Plan period.

(c) and (d) No such proposal has been received from the State of Andhra Pradesh and hence, the question of taking any action does not arise.

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंजाब को आबंटित राशि

1453. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान पंजाब में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों का जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि तुलनात्मक रूप से कम थी; और